BHEL's proposals to tie-up with MNCs

6426. SHRI AAS MOHAMMAD:
SHRI ISH DUTT YADAV:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Public Sector Bharat Heavy Electricals Limited proposes any tie-up with multinational companies for revamping of the power units in the country;

(b) if so, the details of such tie-ups;

(c) the number of power plants in the country which require urgent renovation and modernisation;

(d) whether the company proposes to set up its own financial firm for funding the projects where BHEL bids; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) Yes, Sir.

(b) It would not be in the commercial interest of BHEL to furnish the details at this stage.

(c) The Ministry of Power has informed that the Cental Electricity Authority has approved renovation and modernisation of 34 Thermal Power Stations (TPS) during the Seventh Plan and 47 TPS during the eighth plan period.

(d) and (e) Yes, Sir. The details are being worked out.

श्रम साध्य प्रौद्योगिकियों का विकास

6427. श्री ईश दत्त यादव:
श्री आस मोहम्मद:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार श्रम साध्य प्रौद्योगिकियों की अपेक्षा करती रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नहीं हो तो बेरोजगारों को यथाशीघ्र रोजगार उपलब्ध कराने के लिए श्रम साध्य प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) सरकार ने लघु उद्योग विकास संगठन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग वस्त्र आयुक्त, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) और विकास आयुक्त (हथकरघा) के अधीन विभिन्न संस्थागत नेटवर्क के जरिए प्रौद्योगिकियों का विकास करने के लिए कई उपाय किए हैं। इन संगठनों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र अत्यधिक श्रम प्रधान हैं।

लघु और अत्यन्त छोटे क्षेत्रों के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास और उन्नयन के लिए लघु उद्योग विकास संगठन के अधीन अनेक प्रक्रिया और विकास केन्द्रों, औजार कक्ष और प्रशिक्षण केन्द्रों तथा उत्पाद निर्दिष्ट विशेष संस्थान की स्थापना की गई है। इन संस्थानों में रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय शामिल हैं जो कारीगरों की दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण भी देता है। विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), प्रशिक्षण, विपणन संबंधी कार्यक्रमों का शिल्प विकास केन्द्रों की स्थापना, डिजाइन उन्नयन और शहरी हाटों की स्थापना करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण योजनाएं भी कार्यान्वित करता है।

रोजगार पैदा करने के लिए बेरोजगार व्यक्तियों के लाभ के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं जिनमें प्रधान मंत्री रोजगार योजना, जिलों और ब्लाकों के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के जरिये ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, एकीकृत कॅमर विकास कार्यक्रम परियोजनाएं और ग्रामीण उद्योगों के गहन विकास के लिए योजना शामिल हैं।

2 अक्तूबर, 1993 को शुरू की गई प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अधीन बेरोजगार युवाओं द्वारा सात लाख माइक्रो उद्यम स्थापित करके 10 लाख से ज्यादा व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य है। नीति संबंधी विभिन्न उपायों और कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप श्रम प्रधान क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। उदाहरणार्थ लघु क्षेत्रों में 1992-93 के दौरान 134.05 लाख से बढ़कर 1993-94 के दौरान 139.38 लाख हो गया है। हस्तशिल्प क्षेत्र में रोजगार 1992-93 में 53.05 लाख से बढ़कर 1993-94 में 64.20 लाख हो गया है।